कांग्रेस महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पाली में एनएसयूआई की "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" यात्रा में भाग लिया। उन्होंने रैली में साइकिल चलाकर युवाओं को नशा छोड़ने का संदेश दिया।

सर्कुलर इकॉनमी इन्सैन्टिव के तहत स्टार्टअप को 2 करोड़ रूपए की सहायता मिलेगी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्षेत्रीय "थ्री आर" और सर्कुलर फोरम समारोह को संबोधित किया

- केन्द्रीय आवास मंत्री खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 के तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में कचरा प्रबंधन संयंत्र तथा कचरे से खाद व ऊर्जा बनाने की परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू कराया जायेगा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण क्षमता को 21 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

जयपुर, 3 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकॉनमी अत्यंत प्रभावी माध्यम है। इस व्यवस्था में अपशिष्ट को रिसाइकिल और रियूज किया जाता है जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है।

शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय थ्री आर और सर्कुलर इकॉनमी फोरम समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइक्लिंग को ज्यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही, ट्रीटेड वॉटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दोगुने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट-टू-एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ, और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400 प्रतिशत बढ़ कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6 प्रतिशत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकॉनमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि हम शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकॉनमी एलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 एक ऐसी अनूठी पहल है जो इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया गया है।

कार्यक्रम में जापान, यूएन, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, आंध्रप्रदेश और हरियाणा के शहरी विकास मंत्री, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास विभागों के अधिकारीगण, नगरीय आयुक्त एवं महापौर उपस्थित रहे।

पायलट ने साइकिल चलाकर "नशा छोड़ो जीवन जोड़ो" यात्रा में भाग लिया

एनएसयूआई की साइकिल यात्रा जैसलमेर से जोधपुर, रोहट होते हुए पाली पहुँची

- सचिन पायलट ने कहा कि इस रैली के जरिए अब तक 15 हजार युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई जा चुकी है।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार का अभी तक सवा साल का कार्यकाल मेरी नज़र में निराशाजनक है।

पाली, 3 मार्च, (निसं)। कांग्रेस महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सोमवार को पाली में एनएसयूआई की "नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो" यात्रा का साइकिल चलाकर भाग लिया। यहां से यह साइकिल यात्रा सोजत तक जाएगी। पायलट पाली पहुंचे तो गांधी मूर्ति स्थित कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एनएसयूआई की नशा छोड़ो जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा जैसलमेर से शुरू होकर जोधपुर रोहट होते हुए पाली पहुंची थी।

पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने कहा कि एनएसयूआई की ओर से यह जो नशा छोड़ो, जीवन जोड़ो साइकिल यात्रा जैसलमेर से जयपुर तक निकाली जा रही है, यह कोई चुनावी यात्रा नहीं है और न ही वोट मांगने के लिए निकाली जा रही है। कांग्रेस और एनएसयूआई अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए समाज कल्याण को लेकर यह रैली निकाल रही हैं, जिससे युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके। इस रैली के जरिए अभी तक करीब 15 हजार युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई जा चुकी है।

कार्यक्रम को जोधपुर के सांसद उम्मीदवार रहे करण सिंह ऊंचीयारिडा, रतन देवासी, संगीता बेनीवाल, विधायक भीमराज भाटी, जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने भी संबोधित किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि मुझे अब तक सभी जगह सहयोग मिला है, पाली में युवाओं का अपार जनसमूह देखकर मुझे खुशी हुई है। कार्यक्रम में नसीम बानो, कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष प्रवीण कोठारी, प्रदीप हिंगड़, विधायक भीमराज भाटी, पूर्व विधायक खुशवीर सिंह, पूर्व प्रधान शोभा सोलंकी, नीलम बिरला, हकीम भाई महबूब टी, गणपत पटेल, यशपाल सिंह कुपावत , मांगू सिंह दुधवत, अमीन सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद थे।

इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश की सरकार का अभी तक का सवा साल कार्यकाल मेरी नजर में निराशाजनक है। सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी काम नहीं होने से छाती पीट रहे है। प्रशासन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा मंत्री है या नहीं, यह पता ही नहीं चल रहा। वे इस्तीफा देना चाहते है, लेकिन सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। उनके विभाग में काम नहीं हो रहे। यह प्रदेश की जनता के साथ मजाक हो रहा है। मंत्री मीणा ने जो मुद्दे उठाए, उनका प्रदेश की भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए। रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों की जनेऊ उतारे जाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन उस में उन्हें पर्याप्त कामयाबी नहीं मिली। अभी भी कई विसंगतियां है, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने पर काम कर रही है। शेयर मार्केट हो, बैंक से लोन देने का काम हो, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आर्थिक अपराध हो रहे है, जिनकी परतें अब खुल रही हैं। भाजपा नेताओं को जनता के बीच आकर उनका जवाब देना होगा। राहुल गांधी भी जेपीसी की मांग को लेकर मुद्दा उठा चुके है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की फसल खरीद समय पर नहीं हो रही। कांग्रेस सरकार के समय जो जिले बनाएं गए, उन्हें भाजपा सरकार मनमर्जी से खत्म कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत है। विधानसभा में जनता के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठा रहे है। भाजपा सरकार के मंत्री ढंग से जवाब तक नहीं दे पा रहे।

फिल्म "अनोरा" ने जीते 5 ऑस्कर अवॉर्ड

लॉस एंजलिस, 3 मार्च। 97वें अकादमी पुरस्कार (ऑस्कर) में फिल्म 'अनोरा' का जलवा रहा और उसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित पांच अवार्ड अपने नाम किये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार फिल्म अनोरा के लिये शॉन बेकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रोडी को फिल्म द ब्रुटलिस्ट के लिये मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माइकी मैडिसन को फिल्म अनोरा के लिये दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान कीरन कल्किन को फिल्म ए रियल पेन के लिये दिया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनत्री का पुरस्कार ज़ोई सलदाना, को एमिलिया पेरेज के लिये दिया गया।

विधायक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को सावचेत करने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया हैं कि वे बिना तथ्यों के गैरजिम्मेदाराना बात सदन में नहीं रखें। उन्होंने सदन से आग्रह किया कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ताकि इसकी पूरी जांच की जा सके। इस पर सदन ने प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया।बाद में कांग्रेस विधायकों ने इसका विरोध करते हुए सदन में नारेबाजी की और सदन से बर्हिगमन कर गए।

पेपर लीक मामले में फरार सुरेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पेपर पढ़ाया गया था, वहां भी प्रार्थी मौजूद नहीं था। वह करीब 11 माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने कहा कि प्रार्थी पर पेपर लीक के गिरोह में शामिल होकर काम करने का गंभीर आरोप है। वह फरार चल रहे सुरेश ढाका का भाई और मुख्य अभियुक्त सुरेश विश्नोई का साला है। सुरेश के पकड़ में आने पर प्रार्थी की भूमिका के बारे में अन्य साक्ष्य भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती और एसआई भर्ती में भी उसे गिरफ्तार किया गया है। इसलिए उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

रिपोर्टर्स कलैक्टिव....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्लेटफॉर्म को इन्कम टैक्स विभाग ने पहले चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन के रूप में मान्यता दी थी, हो सकता है कि उस ट्रस्ट को पिछले समय से टैक्स अदा करना पड़े।"

डिजिपब ने कहा, "ऐसे समय जब भारत का प्रैस-स्वतंत्रता सूचकांक अब तक के सबसे नीचे स्तर पर पहुँच गया है तथा मुख्यधारा के मीडिया की लम्बी कतारें सरकार की चियरलीडर्स बन गई हैं, केवल स्वतंत्र मीडिया प्रतिष्ठान ही वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।" बयान में आगे कहा गया, "इनमें से अधिकांश प्रतिष्ठान, जो सरकारी तथा व्यावसायिक विज्ञापनों के बिना स्वयं को जीवित रखे हुये हैं, वित्तीय रूप से लड़खड़ा रहे हैं। सरकार अनगिनत तरीकों, जिनमें कानूनी तथा वित्तीय रास्ते भी शामिल हैं, के जरिए इनका चलते रहना मुश्किल बना रही है। सरकार उन अंतिम चंद गुंजाइशों को भी समाप्त कर रही है, जहाँ पब्लिक आलोचनात्मक कवरेज के लिये पहुँच सकती है।"

ज्ञातव्य है कि "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित वैश्विक प्रैस फ्रीडम इन्डैक्स में वर्ष 2023 में भारत की 180 देशों में 161 वीं रैंक थी। गत वर्ष, यह दो रैंक ऊपर, अर्थात् ,161वें नम्बर पर रही, लेकिन अब भी पड़ोसी देशों, पाकिस्तान (152) तथा श्रीलंका (150) से काफी नीचे है।

'केवल दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक नियुक्ति से वंचित नहीं कर सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित व दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को बाहर रखने के नियम निरस्त किये

- सुप्रीम कोर्ट की डबल बैंच ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों की पात्रता का आकलन करते समय उचित सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये।

नयी दिल्ली, 03 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी (संबंधित पद के आवेदक) को न्यायिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन अभ्यार्थियों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखने वाले मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम की शर्तों के उस भाग को निरस्त करते हुए कहा कि वे (दृष्टिहीन और दृष्टिबाधित) भारत की न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के आवेदन के पात्र हैं। पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने कहा, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियम 1994 के नियम 6ए को निरस्त किया जाता है, क्योंकि यह दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति से बाहर रखता है।

पीठ ने कई पहलुओं पर गौर करने के बाद कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार उनकी (दिव्यांग व्यक्तियों की) पात्रता का आकलन करते समय उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट तौर कहा कि दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले अभ्यर्थी न्यायिक सेवा के पदों के लिए चयन में भाग लेने के हकदार होंगे।

शीर्ष अदालत के समक्ष एक दृष्टिबाधित अभ्यर्थी की मां ने पिछले साल मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम में शामिल उक्त नियम के खिलाफ पत्र याचिका दी थी, जिस पर अदालत ने स्वतः संज्ञान मामला दर्ज किया था।

शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद तीन दिसंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

ट्रंप और ज़ैलैंस्की के बीच फिर संवाद शुरु कराना चाहता है फ्रांस

- फ्रांस और ब्रिटेन ने हवा, समुद्र व ऊर्जा में एक माह के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है।

लंदन/पेरिस, 03 मार्च। फ्रांस और ब्रिटेन ने यूक्रेन में हवा, समुद्र और ऊर्जा अवसंरचना में एक महीने के संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने दैनिक समाचार पत्र ले फेगारो को यह जानकारी दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रविवार को लंदन में यूक्रेन पर शिखर सम्मेलन से पहले घोषणा की कि पेरिस और लंदन युद्ध को रोकने के लिए एक योजना पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि शुरुआत में शत्रुता का अंत करने में जमीनी लड़ाई शामिल नहीं होगी क्योंकि युद्ध विराम के मामले में यह सत्यापित करना बहुत मुश्किल होगा कि मोर्चे का सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय सैनिकों की तैनाती में फ्रांस और ब्रिटेन के सैनिक भाग लेने के लिए तैयार हैं।

मैक्रों ने ले फिगारो को बताया कि आने वाले हफ्तों में यूक्रेनी धरती पर कोई यूरोपीय सैनिक नहीं होंगे। उन्होंने इस समय का उपयोग युद्धविराम वार्ता के लिए करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, हम हर हाल में शांति चाहते हैं लेकिन किसी भी कीमत और बिना किसी गारंटी के।

हाई कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जैन की एकलपीठ ने ये आदेश जब्बार की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए।

सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने अप्रैल, 2024 में बूंदी के सदर थाने में बजरी चोरी के इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। वहीं बनास और चंबल नदी के आसपास के समान मामलों में बजरी माफियाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सीबीआई की ओर से कहा गया कि एक मामले में पूरक आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। बनास और चंबल के आसपास बजरी खनन से जुड़े ऐसे करीब 416 प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वहीं, सीबीआई के पास संसाधनों की कमी और राज्य सरकार की ओर से उचित सहयोग नहीं मिलने के कारण इन प्रकरणों मे सीबीआई जांच करने में समर्थ नहीं है। इसलिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई उच्चस्थ जांच एजेंसी है और वह ही संसाधनों की कमी की बात कह रही है। इसके साथ ही, अदालत ने सीबीआई निदेशक को 17 मार्च को व्यक्तिशः या वीसी के जरिए पेश होकर इस पर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। गौरतलब है कि अदालत ने अप्रैल, 2024 में मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि मामले में कार्रवाई नहीं होने से लगता है कि पुलिस और खान विभाग की बजरी माफिया के साथ मिलीभगत है।

विश्व आदिवासी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा कि इस समुदाय के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए उनकी समस्या पर सबका ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार को उनकी जल-जंगल-जमीन की लड़ाई की मांग स्वीकार कर, नौ अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करना चाहिए।

उन्होंने गोंडी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार उनका ही है, लेकिन भाजपा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर उनकी जमीनों को छीनी रही है। आदिवासियों की ज़रूरत और कानून अलग हैं, इसलिए आदिवासी जिलों में पंचायती राज मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आदिवासी ग्राम सभाओं को दिए कानून सर्वमान्य हैं, जिसका मतलब है कि गांव में स्वशासन इन गांवों के लोगों के माध्यम से होगा।

राजस्थान व तेलंगाना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से 54 हजार मेगावाट से अधिक विद्युत क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2031-32 तक प्राप्त करने की दिशा में दूरगामी निर्णय लिए हैं।

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि राजस्थान की अपार सौर ऊर्जा एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर रही है। तेलंगाना की थर्मल ऊर्जा उत्पादन में दक्षता एवं राजस्थान की असीमित सौर क्षमता के लिए संपादित हुआ यह एमओयू ऊर्जा क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा। ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग तेलंगाना सरकार के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करते हुए इन परियोजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने एक प्रस्तुतीकरण देते हुए एमओयू के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा (तेलंगाना) संदीप कुमार सुल्तानिया, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, आरवीयूएनएल के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के सीएमडी एन. बलराम सहित संबंधित विभागों के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

अमेरिका ने सोच-समझ कर जाल फेंका था, ज़ैलैंस्की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस घटना ने ट्रंप की उस छवि को भी धक्का पहुँचाया, जो एक ऐसे माहिर सौदागर के रूप में बनी हुई थी, जो सबसे जटिल हालात में भी सौदे कर सकता है। ज़ैलैंस्की-ट्रंप बैठक के फ्लॉप होने से अमेरिका को एक मल्टी-मिलियन डॉलर का सौदा गंवाना पड़ा, जिसमें दुर्लभ खनिज जैसे संसाधन शामिल थे, जिन्हें अमरीकी उद्योग लालच से देख रहे थे।

ओवल ऑफिस की झड़प ने डॉनल्ड ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान पहुँचाया है। ट्रंप उम्मीद कर रहे थे कि एक बार जब वह दुश्मनी को ठंडा कर देंगे और रक्तपात खत्म कर देंगे, तो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि वह पुरस्कार बहुत दूर है और नदारद हो गया है।

ट्रंप की पूरी रणनीति असफल साबित हुई, क्योंकि अब तक वह मुख्य रूप से रूस की मांगों को स्वीकार करके एक थोपे गए शांति समझौते को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। यह रणनीति अब उजागर हो गई है और ट्रंप की छुपी हुई योजना विफल हो गई।

डॉनल्ड ट्रंप, यूरोपीय देशों को पूरी तरह से बाहर रखकर एक शांति समझौता करवाने की कोशिश कर रहे थे। ट्रंप इस देश और उसके पड़ोसियों पर एक शांति समझौता थोपना चाहते थे। अब ऐसा लगता है कि किसी भी शांति वार्ता में यूरोपीय शक्तियों को भी शामिल करना होगा।

जब यूरोपीय शक्तियाँ युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौते की रूपरेखा तैयार करेंगी तो आपस में बैठकर करेंगी और अमेरिका को बाद में सूचित करेंगी। हो सकता है कि अमेरिका रूस के साथ मिलकर ऐसे किसी कदम को रोकने की कोशिश करे।

लंदन में यूरोपीय समिट में ज़ैलैंस्की का जो जोरदार स्वागत किया गया और ज़ैलैंस्की की रूसियों के खिलाफ लड़ाई में सराहना की गई, वह ट्रंप द्वारा यूक्रेनी नेता के साथ किए गए व्यवहार को अस्वीकार करने का स्पष्ट संकेत है।

यूरोप में, न केवल ज़ैलैंस्की का स्वागत किया गया, बल्कि किंग चार्ल्स ने भी उनसे मुलाकात की। यह अमेरिकियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि यूरोप को ज़ैलैंस्की उच्चतम स्तर पर भी स्वीकार्य हैं।

यूक्रेन पर विवाद ऐसे समय पर हुआ है जब डॉनल्ड ट्रंप को अपने देश में सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे स्लो हो रही है और कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरे देशों से आने वाले सामानों पर लगाए गए मनमाने शुल्कों के कारण कीमतें और भी बढ़ गई हैं।

अमेरिकी उपभोक्ता महंगाई का सामना कर रहे हैं और रोजगार के लिए बाज़ार ढीला हो गया है। अब तक, रोजगार बढ़ रहा था, लेकिन अब इसके ठंडा होने के संकेत मिल रहे हैं। उपभोक्ता भी अचानक बहुत कम आशावादी नज़र आ रहे हैं।

'नरेगा लोकपाल की अपील सुनने..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के खिलाफ निकाली रिकवरी पर रोक लगा दी है। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने ये आदेश सीमा शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा में पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। गत जुलाई माह में नरेगा लोकपाल ने नरेगा में रोजगार प्रदान करने में असफल रहने पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ करीब साठ हजार रुपए की रिकवरी निकाल कर यह राशि नरेगा मजदूरों को देने के आदेश जारी कर दिए, जबकि याचिकाकर्ताओं ने सभी मजदूरों की ओर से काम मांगते ही जॉब कार्ड जारी कर दिए थे। याचिका में कहा गया कि लोकपाल के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए नियम 13.4 के तहत अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने अब तक अपीलीय प्राधिकरण का गठन नहीं किया है, जिसके चलते लोकपाल की ओर से जारी अवॉर्ड और वसूली आदेशों की अपील नहीं हो पा रही है।

"नार्थ इण्डिया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देना चाहिये। सभी भारतीय भाषाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं तथा सभी समानता के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में कुछ लोग राजनैतिक कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। हमने एन.ई.पी. में यह कहीं नहीं कहा है कि केवल हिन्दी ही पढ़ाई जायेगी।"

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908